

### रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन 17 बहादुर सैनिकों के बलिदान को नमन करती है, जो कल जम्मू-कश्मीर में ऊरी आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। यह हमारे देश की अखंडता पर हमला है और इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए।

साल, 2014 के चुनाव से पहले श्री नरेंद्र मोदी लगातार उस समय की कांग्रेस सरकार को सलाह देते थे कि वो पाकिस्तान को 'प्रेमपत्र' लिखना बंद करे। मोदी जी समय-समय पर '56 इंच की छाती', और 'एक के बदले दस सिर लाने' का जुमला दोहराते थे और सरकार को उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने का परामर्श देते थे, जो भाषा पाकिस्तान समझता है।

प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी 'साड़ी-शॉल' की कूटनीति और श्री नवाज़ शरीफ के साथ जन्मदिन समारोह एवं शादी समारोह में शामिल होने में मशगूल हैं। मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति पूरी तरह से भ्रमित है और किसी भी व्यवहारिक एवं ठोस निष्कर्ष से वंचित है। इस दिशाभ्रष्ट नीति का परिणाम यह हुआ कि कल तक कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग-थलग पड़ा था और आतंकवाद को सुरक्षा देने वाले देशों की सूची में शामिल था, वही पाकिस्तान आज दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने वाले देश के रूप में खुद को पेश कर रहा है। विदेश नीति की इस जबरदस्त असफलता के लिए अकेले प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं।

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि भारत की सीमाएं और देश की सुरक्षा पिछले दो सालों में बहुत कमजोर हो गई हैं। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान ने 900 से अधिक बार सीमारेखा का उल्लंघन किया। ऊधमपुर, गुरदासपुर, पठानकोट और पैम्पोर में पाकिस्तान की ओर से हुए आतंकवादी हमलों में आर्मी और पुलिस के जवानों ने भारी संख्या में अपनी जानें गवाईं, जिनमें कई वरिष्ठतम अधिकारी भी शामिल थे। पठानकोट हवाईबेस पर आतंकवादी हमले में एक दर्जन सैनिकों के जान गंवाने के बावजूद मोदी सरकार ने आईएसआई की अध्यक्षता वाले पाकिस्तानी जांच दल को पठानकोट में आने का निमंत्रण भेज डाला। इस जांच दल ने न केवल भारत की जांच टीम को पाकिस्तान जाकर जांच करने की अनुमति देने से साफ मना किया, अपितु उल्टे भारत पर ही यह आरोप लगा डाला कि पठानकोट हवाई बेस पर हमला करके अपने सैनिकों को मारने का काम खुद भारत ने किया है।

मोदी सरकार ने पुरानी घटनाओं से कुछ भी नहीं सीखा, जिसका घातक परिणाम ऊरी हमले के रूप में देखने को मिला, जिसमें 17 सैनिक शहीद हो गए और 28 से अधिक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और प्रसारित किया गया ऊरी आतंकवादी हमला मोदी सरकार के राजनैतिक नेतृत्व की असफलता की कहानी चीख-चीख कर कह रहा है। रिपोर्ट ने इस मामले में गंभीर इंटेलेजेंस और ऑपरेशनल असफलता स्पष्ट कर दी है। मोदी सरकार को देश की जनता को बताना होगा कि यदि विभिन्न एजेंसियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पहले से ही चेतावनी दे दी थी, तो फिर इस हमले

को रोकने के लिए पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए, जबकि ऊरी ब्रिगेड के मुख्यालय पर हमले की आशंका और नियंत्रण रेखा से इसकी नजदीकी के चलते ये कदम उठाए जाने जरूरी थे? सैनिकों को टेंटों में रखकर दो सैनिक भवन खाली क्यों रखे गए, जिसके चलते कई सैनिकों को जानें गंवानी पड़ीं? सैन्यदल की गतिविधि की यह जानकारी किसने लीक की, कि 10—डोगरा रेजिमेंट, 6—बिहार रेजिमेंट के लिए जगह बना रही है? क्या यह मोदी सरकार की कमांड एवं कंट्रोल संरचना की जबरदस्त असफलता का सबूत नहीं है? क्या प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री, श्री मनोहर पार्रिकर पर इस गंभीर असफलता की जिम्मेदारी तय करने का साहस एवं प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे?

भारत के 125 करोड़ नागरिकों की ओर से हम प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करते हैं कि वो 'जुमलों' की दुनिया से बाहर आकर 'वास्तविकता' को पहचानें और 'स्वयं का गुणगान' करने की जगह 'देशहित एवं सुरक्षा के लिए काम' करें। ऊरी हमले में भारत सरकार को एक कड़ा एवं उचित उत्तर देने की जरूरत है। मोदी सरकार को पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के रूप में अलग-थलग करके, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जाना चाहिए।